भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5533

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

एक राष्ट्र, एक उर्वरक का प्रभाव

5533. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर तेलंगाना में छोटे और सीमांत किसानों पर एक राष्ट्र, एक उर्वरक (ओएनओएफ) योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या तेलंगाना में किसान संगठनों द्वारा एकल ब्रांड के तहत उर्वरको के मानकीकरण के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है और यदि हां, तो उनके साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से तेलंगाना में मृदा उर्वरता और फसल उपज अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए ओएनओएफ ढांचे के तहत क्षेत्र-विशिष्ट उर्वरक अनुकूलन कार्यक्रम स्थापित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): दिनांक 24 अगस्त 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी स्कीम के तहत उर्वरकों के लिए एकल भारत ब्रांड और लोगो की शुरूआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक (ओएनओएफ) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता बास्केट में वृद्धि करना है; बाजारों में उपलब्ध कई ब्रांडों में से चयन करने में किसानों को होने वाली दुविधा को दूर करना है ताकि क्रिसक्रॉस संचलन को कम किया जा सके और उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने पीएमबीजेपी शुरू करने से पहले सार्वजनिक और निजी उर्वरक

कंपनियों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया था। तथापि, सरकार ने देश में छोटे और सीमांत किसानों पर एक राष्ट्र, एक उर्वरक (ओएनओएफ) स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ख): जी नहीं, इस तरह का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): भारत सरकार उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है और इसके अतिरिक्त उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 20 बी के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग फसल विशिष्ट और मृदा अनुकूलित विशिष्ट उर्वरकों को उनकी जैव-प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करता है। वर्तमान में, राज्यों के विभिन्न जिलों तेलंगाना (गन्ना टॉप ड्रेसिंग, गन्ना बेसल, ऑयल पाम बेसल, मक्का बेसल, मक्का टॉप ड्रेसिंग, राइस बेसल, राइस टॉप ड्रेसिंग) और अन्य राज्य नामतः उत्तर प्रदेश (गन्ना बेसल, आलू बेसल, गेहूं बेसल, धान बेसल), उत्तराखंड (गन्ना बेसल), आंध्र प्रदेश (गन्ना बेसल, ऑयल पाम बेसल, मक्का बेसल, मक्का टॉप ड्रेसिंग, राइस बेसल, राइस टॉप ड्रेसिंग), तमिलनाडु (गन्ना टॉप ड्रेसिंग, गन्ना बेसल), महाराष्ट्र (गन्ना टॉप ड्रेसिंग, गन्ना बेसल, प्याज बेसल, लाल चने बेसल, मक्का बेसल, कपास, केला), बिहार (मक्का बेसल) और पश्चिम बंगाल (धान बेसल, आलू बेसल) सहित राज्यों के विभिन्न जिलों के लिए 30 अनुकूलित उर्वरक मान्य हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए फसल विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र विशिष्ट उर्वरक संबंधी सिफारिशें तैयार की हैं। प्रमुख फसलों के लिए मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया पर नेटवर्क कार्यक्रम के माध्यम से किसी विशिष्ट आदान और मृदा की स्थिति के लिए फसल उपज का इष्टतमीकरण भी किया जाता है।

******